प्रधानमंत्री आज किसान सम्मान निधि की किश्त बैंक खातों में स्थानांतरित करेंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल दुर्गापुरा से इस समारोह में शामिल होंगे, सभी जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे

- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान की अब तक जारी हुई 20 किश्तों में राजस्थान के कृषकों को 25 हजार 142 करोड़ रूपए की राशि हस्तांतरित हो चुकी है।**

जयपुर, 18 नवम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19 नवम्बर को 'पीएम-किसान उत्सव दिवस' के अवसर पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा से शामिल होंगे। साथ ही, राज्य के सभी जिलों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत से लेकर अब तक 20 किश्त जारी की जा चुकी हैं। जिससे राज्य के कृषकों को 25 हजार 142 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित हुई है। साथ ही, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 4 किश्तों के माध्यम से 2 हजार 73 करोड़ रुपये की राशि भी राज्य के किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।

कार्यक्रम के तहत पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से राज्य के 66 लाख 62 हजार किसानों को 1 हजार 332 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की राशि तीन समान किश्तों में प्रदान की जाती है। राजस्थान में किसानों को अतिरिक्त राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू है, जिसके अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 3 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि दी जा रही है।

बिहार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विधायक दल की बैठक की निगरानी और नेतृत्व चयन प्रक्रिया पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। यह टीम विधायकों की राय जुटाने के साथ ही, अगले नेता के चयन की प्रक्रिया को सुचारु बनाने में मदद करेगी। सूत्रों के मुताबिक राजग के अन्य दल भी अपना नेता चुनेंगे। इसके बाद राजग विधायकों की एक बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। जिसके बाद कुमार राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

अल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त होने का फर्जी दावा किया, जिससे छात्रों, अभिभावकों और अन्य स्टेकहोल्डर्स को भ्रमित कर गलत तरीके से लाभ कमाया गया। एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि विश्वविद्यालय ने यूजीसी एक्ट, 1956 की सेक्शन 12(ब) के तहत मान्यता प्राप्त होने का झूठा दावा फैलाया, जबकि वास्तव में यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी केवल सेक्शन 2(एफ) के अंतर्गत, राज्य के निजी विश्वविद्यालय के रूप में शामिल है।

सऊदी में ही दफन होंगे 45 भारतीय ज़ायरीनों के शव

तेलंगाना सरकार हर व्यक्ति के परिवार से दो लोगों को सऊदी अरब भेजेगी

- **सऊदी अरब के नियमों के अनुसार उमराह शुरु करने से पहले ज़ायरीन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं कि उनकी मृत्यु सऊदी में हो जाए तो उन्हें वहीं दफनाया जाए।**
- **सऊदी नियमों के अनुसार मृतकों के परिजनों को मुआवज़ा मिलना भी मुश्किल है इसमें लंबी कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ती है।**

रियाद, 18 नवम्बर। सऊदी अरब के मक्का-मदीना हाईवे पर हुए भीषण बस हादसे ने भारत के कई परिवारों को गहरा सदमा पहुंचाया है। यह दुर्घटना तब हुई, जब उमराह के लिए जा रही यात्रियों से भरी एक बस को पीछे से एक तेज रफ्तार फ्यूल टैंकर ने टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे में 45 भारतीय नागरिकों की जान चली गई, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे और इनमें से अधिकतर हैदराबाद के रहने वाले थे। इस दुखद घटना के बाद तेलंगाना मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला लिया है कि मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर को अब भारत नहीं लाया जाएगा।

तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि बस हादसे में जान गंवाने वाले 45 भारतीय तीर्थयात्रियों के शवों को, उनके धार्मिक रिवाजों के अनुसार, सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा। यह निर्णय सऊदी अरब के कानून और हज एवं उमराह मंत्रालय के नियमों को देखते हुए लिया गया है। नियमों के मुताबिक, जो तीर्थयात्री यात्रा शुरू करने से पहले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, उनकी मृत्यु सऊदी की जमीन पर होने पर शवों को वहीं दफनाया जाता है। सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए एक भावुक कदम उठाया है। हर मृतक परिवार से दो सदस्यों को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सऊदी अरब भेजा जाएगा। भारत सरकार रियाद में भारतीय दूतावास के जरिए स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है, ताकि सभी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। मृतक परिवारों को तुरंत मुआवजा मिलना भी काफी कठिन है। सऊदी अरब में सड़क दुर्घटनाओं में सरकार की ओर से कोई सीधा मुआवजा नहीं दिया जाता। मुआवजा तभी मिल सकता है, जब पुलिस की जांच में यह साबित हो जाए कि दुर्घटना टैंकर ड्राइवर या उसकी कंपनी की गलती से हुई थी। गलती साबित होने के बाद भी परिवार को कानूनी दावा दायर करना होगा।

थरूर ने फिर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रविशंकर प्रसाद के साथ बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से बैठे दिखाई दे रहे थे। उनके दूसरी ओर कांग्रेस छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद बैठे थे।

थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण का एक बड़ा हिस्सा "मैकाले की 200 साल पुरानी गुलाम मानसिकता की विरासत को उलटने "पर केन्द्रित था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की विरासत, भाषाओं और ज्ञान परंपरा में स्वाभिमान लौटाने के लिए 10 साल का राष्ट्रीय अभियान चलाने की अपील की।

थरूर ने कहा, "कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री का भाषण आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक आ ान, दोनों का मिला-जुला रूप था, जिसने देश को विकास के लिए बेचैन रहने का आग्रह किया। मुझे कार्यक्रम में उपस्थित होकर खुशी हुई..."

प्रधानमंत्री 19वीं सदी के ब्रिटिश सांसद थॉमस बैबिंगटन मैकाले का जिक्र कर रहे थे, जो 1834 में भारत आए थे और जिन्हें देश में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है, जिसमें पूरे देश के सभी स्कूलों में अंग्रेजी को अधिकारिक भाषा बनाना भी शामिल था।

प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत की पुरानी शिक्षा प्रणाली में हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया जाता था। पढ़ाई के साथ कौशल भी सिखाया जाता था। इसलिए मैकाले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ को तोड़ने का फैसला किया... और वह इसमें सफल रहा।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "मैकाले ने यह सुनिश्चित किया कि उस दौर में ब्रिटिश भाषा और ब्रिटिश सोच को ज़्यादा मान्यता मिले, और भारत को इसकी क़ीमत सदियों तक चुकानी पड़ी। उसने हमारा आत्मविश्वास तोड़ा और हमें हीन भावना से भर दिया।"

थरूर द्वारा की गई प्रधानमंत्री के भाषण की प्रशंसा भी कांग्रेस नेताओं को पसंद आने की संभावना कम है, क्योंकि यह पहला अवसर नहीं है, जब उन्होंने प्रधानमंत्री की इतनी खुलकर तारीफ़ की है।

चार बार सांसद रहे थरूर और कांग्रेस के रिश्ते पिछले कुछ महीनों में तेज़ी से बिगड़े हैं, खासकर तब से, जब अप्रैल 22 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्हें सरकार के प्रतिनिधिमंडल में विपक्ष का चेहरा बनाया गया था।

थरूर ने अमेरिका और चार अन्य देशों के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था और वापस लौटने पर उनकी मुलाकात सौहार्दपूर्ण (दोस्ताना) अन्दाज़ में प्रधानमंत्री से हुई थी, जिसके बाद उनके दल बदलने की अटकलें और तेज हो गई थीं।

'अमेरिका के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि रिश्तों में कोई गतिरोध है। दोनों देशों के बीच संबंध बहुत महत्वपूर्ण और रणनीतिक बने हुए हैं।"

गोयल ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका के साथ हाल ही में हुआ एलपीजी आयात समझौता कई वर्षों का हो सकता है, जो दोनों देशों की मजबूत मित्रता और बढ़ती साझेदारी को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "हमने अभी-अभी एक बड़ा एलपीजी समझौता किया है, जिसके तहत हर साल 2.2 मिलियन टन एलपीजी का आयात लम्बे समय तक किया जाएगा। यह एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है और दोनों देश परस्पर व्यापार और वाणिज्य बढ़ाने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।" यह वार्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने और रूसी कच्चे तेल पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने के बाद, दोनों देशों के बीच के संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गये थे। प्रस्तावित व्यापार समझौते का लक्ष्य दोनों देशों के बीच व्यापार को वर्तमान 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक करना है। अमेरिका, भारत के बाजार में बादाम, पिस्ता, सेब, एथेनॉल और जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पादों जैसे सामानों की अधिक पहुंच बनाना चाहता है। वर्ष 2024-25 में, अमेरिका लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा तथा दोनों देशों के बीच 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें 86.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात शामिल है। यह भारत के कुल माल निर्यात का लगभग 18 प्रतिशत, आयात का 6.22 प्रतिशत और कुल व्यापार का 10.73 प्रतिशत है।

'राहुल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सिर्फ दिखावा और ध्यान भटकाने की रणनीति में ही रुचि रखते हैं।

मुख्य समस्या यह है कि राहुल गांधी व्यवहारिक नेता नहीं हैं। वे चुनावों की बारीकियों को संभालने या रणनीति बनाने में उस स्तर पर सक्रिय नहीं हैं, जैसा भाजपा के बड़े नेता करते हैं। उन्हें उनकी ही रणनीति में मात देना राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा और कठिन काम है, जिसके लिए न उनके पास धैर्य है, और न ही राजनीतिक कौशल।

और दुख की बात यह है कि उनके पास ऐसे समर्पित लोग भी नहीं हैं, जो इस काम को संभाल सकें।

20 नवंबर को दसवीं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से रहेंगे। चिराग पासवान की एलजेपी (आरवी) को दो मंत्री मिलने की संभावना है, जबकि एचएएम-एस और आरएलएम को एक-एक पद मिलेगा। खबरों के अनुसार, चिराग तीन पदों की मांग कर रहे हैं किन्तु उन्हें कम पर सहमत करवाने की कोशिश जारी है। नए मंत्रिमंडल में लगभग आधा दर्जन नए चेहरे शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा भी होंगे, जो महनार सीट से जीते हैं।

गौरतलब बात यह है कि नए मंत्रिमंडल में जेडीयू की हिस्सेदारी पहले से काफी अधिक होगी। पिछली सरकार में भाजपा के बाईस मंत्री थे, जबकि जेडीयू के सिर्फ बारह। इस बार दोनों दल लगभग बराबरी पर हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 89 विधायक हैं, जेडीयू के 85, एलजेपी (आरवी) के 19, एचएएम-एस के पाँच और आरएलएम के चार। पिछली विधानसभा में भाजपा के पास 74 सीटें और जेडीयू के पास 43 सीटें थीं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री के साथ कुल 20 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। इनमें भाजपा और जेडीयू में से प्रत्येक के लगभग 6-7 मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा एलजेपी (आरवी) के दो मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आएलएम) से भी एक-एक मंत्री शपथ लेंगे।

देश भर के नेताओं की मौजूदगी में, 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाला नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह बड़े स्तर पर होगा, पर इतने बड़े स्तर पर होने वाला यह पहला समारोह नहीं है। 2005 के बाद से हुए चुनावों के बाद, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ चार बार ली है, जिनमें से तीन बार शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में ही हुआ है। यह स्थल स्वतंत्रता पूर्व से ही बड़े और महत्वपूर्ण आयोजनों का साक्षी रहा है।

20 नवंबर के शपथ-ग्रहण समारोह में नीतीश दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

आरिफ़ मोहम्मद, नीतीश कुमार को शपथ दिलाने वाले पिछले ढाई दशक में आठवें राज्यपाल होंगे। वर्ष 2000 में वी.सी. पांडे ने उन्हें पहली बार शपथ दिलाई थी, और 20 नवंबर 2025 को आरिफ़ मोहम्मद खान शपथ दिलाएंगे। इन वर्षों में बूटा सिंह, देवानंद कोंवर, रामनाथ कोविंद, केसरी नाथ त्रिपाठी, फागू चौहान और राजेन्द्र विशाल अरलेकर भी उन्हें शपथ दिला चुके हैं। 2015 के बाद, अक्सर परिवर्तित हुए राजनैतिक गठजोड़ों के कारण, त्रिपाठी और चौहान ने उन्हें दो-दो बार शपथ दिलाई थी।

'एआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर अपनी राय दी है। लेकिन वित्तीय इतिहास बताता है कि ऐसी कोई भी बड़ी गिरावट व्यापक आर्थिक संकट का कारण बन सकती है।

हालांकि पिचाई ने अपने शब्दों में क्या संकेत दिया है यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह मानना गलत नहीं होगा कि ए.आई. क्षेत्र में कोई अचानक रुकावट आई, तो इसका असर तेजी से पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और एक गंभीर वित्तीय संकट भी पैदा हो सकता है।

यह और भी संभव है क्योंकि आज के वित्तीय बाज़ार और अर्थव्यवस्थाएँ पहले से कहीं ज्यादा एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए, जैसा पिचाई संकेत देते हैं, बेहतर होगा कि हम संभलकर आगे बढ़ें और उम्मीद रखें कि हालात अच्छे रहें।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908